

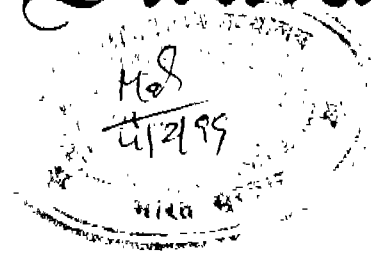


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 490]
No. 490]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 1998/अग्रहायण 25, 1920
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 1998/AGRAHAYANA 25, 1920

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1998

सा. का. नि. 746 (अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 § 1985 का 13§ की धारा 35 की उपधारा 2§ के अन्तर्गत § ग§ और धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण § अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें § नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. इन नियमों का नाम तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण § अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें § संशोधन नियम, 1998 है ।

2. तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण § अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें § नियम, 1988 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है § के नियम 3 के

स्थान पर, निम्नलिखित नियम 01 जनवरी, 1996 को प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

"3 वेतन - अध्यक्ष छब्बीस हजार रुपये प्रतिमास के वेतन और एक हजार रुपये प्रतिमास के विशेष भत्ते का हकदार होगा, उपाध्यक्ष छब्बीस हजार रुपये प्रतिमास के वेतन का हकदार होगा तथा सदस्य 22,400-600-26,000 रुपये प्रतिमास के वेतनमान में वेतन का हकदार होगा :

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के मामले में, जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा-निवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य-सरकार के अधीन सेवा से सेवा-निवृत्त हुआ है या जो पेंशन या उपदान या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवा-निवृत्ति फायदे या अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है तो उसके वेतन से उसके द्वारा प्राप्त पेंशन या उपदान के समतुल्य पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदे, यदि कोई हों की सकल रकम कम कर दी जाएगी, किन्तु इसमें से उसके द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्त किए जाने वाले सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन कम नहीं की जाएगी ।"

3. उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 01 जनवरी, 1996 को प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

"4. महंगाई-भत्ता - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपने वेतन के अनुरूप, ऐसी दरों पर महंगाई भत्ते के हकदार होंगे जो 22,400-600-26,000 रुपए या उसके ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय है ।"

4. उक्त नियमों में यथा संशोधित नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 01 अगस्त, 1997 को अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

"4क. नगर प्रतिपूर्ति भत्ता - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपने वेतन के अनुरूप ऐसी दरों पर नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के हकदार होंगे जो 22,400-600-26,000 रुपए या उससे ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय है ।"

5. उक्त नियमों के नियम 6 के उप नियम 33 में, "240" अंकों के स्थान पर "300" अंक 01 जुलाई, 1997 को प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे ।

6. उक्त नियमों के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 01 अक्टूबर, 1997 को प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात्:-

"11. छुट्टी-यात्रा-रियायत- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य, उन्हीं दरों पर और उन्हीं मापमानों और उन्हीं शर्तों पर जो 22,400-600-26,000 रुपये या उससे ऊपर के वेतनमान में वेतन

पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों के संबंध में लागू है, छुट्टी-यात्रा-रियायत का हकदार होगा।"

स्पष्टीकारक टिप्पण :-

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, छुट्टी, छुट्टी-यात्रा-रियायत तथा उन्हें अनुज्ञेय अन्य भत्तों के संबंध में पश्चिमे केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिशों लागू करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने भिन्न-भिन्न प्रभावी तारीखों से निर्णय लिए हैं। तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को अनुज्ञेय वेतन और अन्य भत्ते आदि के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने उन्हीं वरों पर और उन्हीं मापमानों और उन्हीं शर्तों पर वेतन और भत्ते का पुनरीक्षण अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया है जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में अनुज्ञेय है। अतः नियमों में संशोधन भूतलकी प्रभाव से किया जाना अपेक्षित है। उक्त नियमों के उपबंधों को भूतलकी प्रभाव विरुद्ध जाने से किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[फा. सं. ए-11014/26/98-प्र. अ.]

रमेश कुमार टण्डन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :-

मूल नियम, अधिसूचना सं० सा.का.नि. 756 §अ§, तारीख 29 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें निम्नलिखित सं० द्वारा संशोधन किए गए :-

§1§ सा.का.नि. 1047 §अ§, दिनांक 13.12.1989

§2§ सा.का.नि. 147 §अ§, दिनांक 31.01.1994

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 1998

G.S.R. 746(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 35 and section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1988, namely:—

1. These rules may be called the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1998.

2. In the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1988 (hereinafter referred to as the said

rules), for rule 3, the following rule shall be deemed to have been substituted on the 1st day of January, 1996, namely:—

"3. Pay.--- The Chairman shall be entitled to a pay of twenty six thousand rupees plus a special allowance of one thousand rupees per mensem, a Vice-Chairman shall be entitled to a pay of twenty six thousand rupees per mensem and a Member shall be entitled to a pay in the scale of pay of Rs. 22,400-600-26,000 per mensem:

Provided that in the case of appointment as a Chairman, a Vice-Chairman or a Member of a person who has retired as a judge of High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension or gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension or pension equivalent to gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent to retirement gratuity, drawn or to be drawn by him."

3. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be deemed to have been substituted on the 1st day of January, 1996, namely:—

"4. Dearness allowance.-- The Chairman, a Vice-Chairman and a Member shall be entitled to dearness allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' Officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 22,400-600-26,000 or above."

4. In the said rules, after rule 4 as so amended, the following rule shall be deemed to have been inserted on the 1st day of August, 1997, namely:—

"4A. City compensatory allowance.-- The Chairman, a Vice-Chairman and a Member shall be entitled to city compensatory allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' Officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 22,400-600-26,000 or above."

5. In the said rules, in rule 6, in sub-rule(3), for the figures "240", the figures "300" shall be deemed to have been substituted on the 1st day of July, 1997.

6. In the said rules, in rule 11, for the portion beginning with words "applicable" and ending with the words "or above", the words, letters and figures "admissible" to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 22,400-600-26,000 or above." shall be deemed to have been substituted on the 1st day of October, 1997.

Explanatory note.---- With a view to implement the recommendations of the Fifth Central Pay Commission regarding Central Government employees' scales of pay, leave, leave travel concession and other allowances admissible to them, the Central Government took decisions for different effective dates. In respect of pay and other allowances, etc., admissible to the Chairman, Vice-Chairman and Members of the Tamil Nadu Administrative Tribunal, the Central Government decided to allow the revision of pay and allowances at the same rates, at the same scales and on the same conditions as are admissible to the Central Government employees. Therefore, the amendments in the rules are to be given a retrospective effect. By giving this retrospective effect to the provisions of these rules, no one is likely to be affected adversely.

[F. No. A-11014/26/98-AT]

R. K. TANDON, Jt. Secy.

Foot Note:— The principal rules were published vide notification No.G.S.R. 756(E), dated the 29th June, 1988 and subsequently amended vide No.--

(1) G.S.R. 1047(E), dated the 13th December, 1989.

(2) G.S.R. 47(E), dated the 31st January, 1994

339461/98-2

